



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362]
No. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 1980/श्रावण 10, 1902
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 1980/SRAVANA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आवेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1980

का०आ० 603(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का०आ० सं० 422 (अ) तारीख 5 अगस्त, 1975 (जिसे इसमें इसके प्रागे अक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को संमत् होजेल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) 5 अगस्त, 1975 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश सं० का०आ० 292(अ) तारीख 16 मई, 1979 द्वारा सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार (जिसे इसमें इसके प्रागे प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को पूर्वोक्त व्यक्तियों के निकाय से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 5 अगस्त, 1975 से जेय पांच वर्ष की अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोक हित में यह समीचीन है औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास एक वर्ष की प्रतिरिक्त अवधि तक बना रहे अद्यो (विकास और वित्तियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ब क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उस प्रभाव की अनुज्ञा के लिए निवेदन करने हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया था, और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 14 जुलाई, 1980 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी थी;

537 G.I/80

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और वित्तियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ब क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश करती है कि उक्त आदेश एक वर्ष की प्रतिरिक्त अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[का०सं० 2 (17)/80-सी०यू०सी०]

ब० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st August, 1980

S.O.603(E).—whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No.S.O.422(E), dated the 5th August, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over the industrial undertaking known as the Messrs. Engel India Machine and Tools Limited, Calcutta (hereafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of 5 years from the 5th August, 1975;

And whereas the Central Government vide its Order No. S.O.292(E), dated the 16th May, 1979, authorised the Secretary Closed and Sick Industries, Department of the Government of West Bengal (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the said industrial undertaking from the aforesaid body of persons for the remaining period of five years from the 5th August, 1975;

And whereas the Central Government being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised persons should continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year, made an application to the Calcutta High Court praying for permission to that effect, under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and that the said High Court has, by its Order dated the 14th July, 1980, granted the said permission;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year.

[F.No.2(17)/80-Cus.]

B. ROY, Jt. Secy.